बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 245 ● नई दिल्ली ● बुधवार 01 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

चैतन्यानंद के फोन में मिली एयरहोस्टेस की तस्वीरें, पुलिस बोली- पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा

नई दिल्ली। दिल्ली में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किए चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल फोन में कई एयरहोस्टेस की भी पुलिस को तस्वीरें मिली हैं। चैतन्यानंद ने उन एयरहोस्टेस के साथ फोटो खिंचवा रखी है। डीसीपी दक्षिण पश्चिम जिला का कहना है कि वह पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पूछताछ के दौरान लगातार झूठ बोल रहा है। उसकी दो महिला सहयोगियों को भी हिरासत में लेकर उसके साथ चैतन्यानंद का आमने-सामना करवाया जा रहा है।

वीके मल्होत्रा को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे पीएम मोदी, सीएम रेखा गुप्ता ने जताया शोक

नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का मंगलवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वे 94 साल के थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1931 को लाहौर शहर में हुआ था। वीके मल्होत्रा दिल्ली के पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद और सांसद रह चुके हैं। कुछ दिनों से वह एम्स में भर्ती थे। जहां उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह लगभग 6 बजे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पीएम मोदी ने उनके घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने दी जानकारी

इस मौके पर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि अत्यंत दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी का आज प्रातः आकस्मिक निधन हो गया है। वह 94वें वर्ष के थे। आगे कहा कि प्रो. विजय मल्होत्रा जी का जीवन सादगी एवं जन सेवा को समर्पण की मिसाल रहा, उन्होने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए जनसंघ काल से बहुत काम किया। उनका जीवन हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को सदैव प्रेरणा देता रहा है और देता रहेगा। वीके मल्होत्रा के निधन पर पीएम मोदी, सीएम रेखा से लेकर कई भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया।

हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए अथक परिश्रम किया- राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि जनसंघ और भाजपा के इतिहास में प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जैसे दिग्गजों का विशेष स्थान है। उन्होंने दिल्ली में हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए अथक परिश्रम किया। भारतीय संविधान के अपने ज्ञान के लिए व्यापक रूप से सम्मानित, वे एक अनुभवी सांसद थे जिन्होंने जनता के बीच अथक परिश्रम किया। उनके निधन से मुझे गहरा दुःख हुआ है। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं।

संगठन को विस्तार देने में भूमिका निभाई – सीएम योगी

वीके मल्होत्रा के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी का निधन अत्यंत दुःखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

सीएम रेखा गुप्ता ने वीके मल्होत्रा को किया याद

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सभी कार्यकताओं के अभिभावक और दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी का निधन अत्यंत पीड़ादायक और अपूरणीय क्षति है। जनसंघ के दौर से लेकर भाजपा की स्थापना तक उनका जीवन राष्ट्रनिष्ठा, संगठन कौशल और अनुशासन का जीता-जागता उदाहरण रहा। दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन की नींव को मजबूत किया और असंख्य कार्यकर्ताओं को सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाया। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।

सम्मान, अवसर और अधिकार : सीएम रेखा का एलान, जल्द बनेगा ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड; किन्नर समुदाय बनेगा आत्मनिर्भर

नई दिल्ली । मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार जल्द ही ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन करेगी, जिसमें इस समुदाय के प्रतिनिधि और कार्यकारी सदस्य दोनों शामिल होंगे। इस बोर्ड से उनकी समस्याओं को समझकर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी नेशनल ट्रांसजेंडर अवार्ड्स कार्यक्रम में दी। अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर अखाड़ा की ओर से अर्धनारीश्वर थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2019 में लागू किए गए ट्रांसजेंडर एक्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कानून किन्नर समुदाय की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास केवल एक नारा नहीं, बल्कि सरकार का सच्चा संकल्प है। ये समाज के हरएक वर्ग को समान अवसर देने पर आधारित है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार किन्नर समुदाय की समस्याओं को समझेगी और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किन्नरों को समान सम्मान, अवसर और अधिकार मिलें, ताकि वे आत्मनिर्भर और सशक्त समाज का निर्माण कर सकें। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, विधायक शिखा राय सहित देशभर से आए प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि स्त्री और पुरुष दोनों के बिना संपूर्णता संभव नहीं है। इसी संतुलन और सामंजस्य में मानवता का वास्तविक स्वरूप छिपा है।

कोर्ट को सीसीटीवी में ऐसा क्या दिखा? आरोपी महिला गगनप्रीत कौर को मिली जमानत

नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में हुई बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में आरोपी महिला गगनप्रीत को ज़मानत दे दी है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के बयानों में स्पष्ट विरोधाभास है। अदालत ने कहा कि दुर्घटना के सीसीटीवी फुटेज ने शुरुआती आकलन को बदल दिया है, जिससे गैर इरादतन हत्या का आरोप कमज़ोर पड़ गया है और यह संकेत मिलता है कि दुर्घटना शायद तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला हो सकता है।

अदालत ने कहा कि एफआईआर में दर्ज यह दावा कि बीएमडब्ल्यू ने मोटरसाइकिल को पीछे से सीधी टक्कर मारी थी, सबूतों से समर्थित नहीं है।

सीसीटीवी फुटेज में कार का नियंत्रण खोना, डिवाइडर से टकराना, पलटना और इस प्रक्रिया में एक मोटरसाइकिल और बस से टकराना दिखाया गया है।

अदालत ने कहा, फुटेज जानबूझकर तेज़ गति से मोटरसाइकिल से टक्कर मारने के दावे का समर्थन नहीं करता। अदालत ने आगे कहा कि यह दृश्य गैर इरादतन हत्या (संभावित परिणामों की जानकारी के साथ मौत का कारण बनना) से ज्यादा लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसा लग रहा है। अदालत ने यह भी बताया कि दुर्घटनास्थल पर स्पीड कैमरों की निगरानी होने के बावजूद, अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि कार कितनी तेज़ चल रही थी। अदालत ने दुर्घटनास्थल के ठीक पीछे मौजूद एम्बुलेंस कर्मचारियों के आचरण की कड़ी आलोचना की। हालाँकि वे कुछ ही सेकंड में पहुँच गए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि ड्राइवर और पैरामेडिक ने न तो पीड़ित की नब्ज देखी और न ही कोई प्राथमिक उपचार दिया। इसके बजाय, वे 40 सेकंड के भीतर ही घटनास्थल से चले गए। उनके व्यवहार को अत्यधिक गैर-पेशेवर और अनैतिक बताते हुए अदालत ने कहा कि इससे अभियोजन पक्ष का स्वर्णिम समय सिद्धांत कमजोर हो गया है कि पीड़ित की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसे समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिली।

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो मौत के सही समय और कारण की पुष्टि कर सकती है, अभी तक दाखिल नहीं की गई है। अदालत ने कहा कि आरोपी पीड़िता की सचमुच मदद करने की कोशिश कर रही थी या सिर्फ अपने पक्ष में सबूत गढ़ रही थी, यह जाँच और मुकदमे का विषय है।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज

नई दिल्ली ।

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मंगलवार को अचानक हुई बारिश ने लोगों को चौंका दिया. दिल्ली के पटेल नगर इलाके में बारिश की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हो गया। वहीं नोएडा में झमाझम बारिश की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई। जबकि महर्षि नगर रामलीला ग्राउंड में बारिश का पानी भर गया। इसके अलावा गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी बारिश हुई । दरअसल, बीते कई दिन से उमस और गर्मी ने दिल्लीवासियों की हालत खराब कर रखी थी. हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी. खड़े-खड़े पसीने से तरबतर होने वाली स्थिति थी. इस बीच मौसम विभाग ने दो दिन की राहत के आसार जताए थे. मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, मंगलवार और बुधवार (30 सितंबर और 1 अक्टूबर) को हल्की बारिश के साथ तापमान में अच्छी-खासी गिरावट के आसार हैं. ऐसे में दिल्ली वालों के लिए यह मौसम बड़ी राहत लेकर आ रही है. लंबे समय से चुभती धूप और उमस भरी गर्मी के बीच आई इस बरसात से जहां लोगों ने राहत महसूस की, वहीं मौसम विभाग का कहना है कि यह बरसात मानसून का हिस्सा नहीं है. मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार के मुताबिक मानसून दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट से विदा हो चुका है. फिलहाल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने निम्न दबाव क्षेत्र की वजह से बारिश हो रही है. डॉ. कुमार ने बताया कि इसी सिस्टम के कारण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है. हालांकि यह स्थिति यादा दिनों तक नहीं रहेगी. उन्होंने कहा, कल और परसों तक हल्की-फुल्की बारिश रहेगी, लेकिन इसके बाद सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा. 4 अक्टूबर तक गर्मी बनी रहेगी और उसके बाद ही तापमान में गिरावट शुरू होगी.

नॉर्थ वेस्ट में तापमान सामान्य से अधिक

मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में रात का तापमान इस समय सामान्य से 3-5 डिग्री अधिक दर्ज हो रहा है. इसका कारण अरब सागर से आने वाली गर्म और नमी वाली हवाएं हैं. दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे नॉर्थ वेस्ट में कम से कम 4 अक्टूबर तक यही स्थिति रहने वाली है. उसके बाद ही तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी. इसी बीच गुजरात के तटीय इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है. कच्छ की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी है.

पूर्वी भारत में भी हो सकती है बारिश

2 अक्टूबर से पूर्वी भारत में बारिश का अनुमान है. बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश खरीफ फसलों के लिए मददगार साबित हो सकती है, हालांकि यादा बरसात से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है.

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और हिमालयी क्षेत्र में अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 4 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में दस्तक देगा. इसके असर से दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एक बार फिर से हल्की बारिश हो सकती है. वहीं 6 अक्टूबर को इसका प्रभाव पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में दिखेगा. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका है.

चिदंबरम का 26/11 पर कबूलनामा: अमेरिकी दबाव में पीएम ने नहीं की पाकिस्तान पर कार्रवाई, बीजेपी हुई हमलावर

नई दिल्ली ।

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने स्वीकार किया है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव, खासकर संयुक्त राय अमेरिका के दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख के कारण पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला किया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि हालाँकि बदला लेने का विचार मेरे मन में आया था, लेकिन सरकार ने सैन्य कार्रवाई न करने का फैसला किया। हालांकि, उनकी यह टिप्पणी भाजपा को रास नहीं आई और उन्होंने इस स्वीकारोक्ति को बहुत कम और बहुत देर से लिया गया बताया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा, पूरी दुनिया दिल्ली में यह कहने आई थी कि युद्ध शुरू मत करो। हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया को याद करते हुए, जिसमें विदेशियों सहित 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उन्होंने कहा कोंडोलीज़ा राइस, जो उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री थीं, मेरे कार्यभार संभालने के दो-तीन दिन बाद मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने आईं।

और कहने आईं, कृपया प्रतिक्रिया न दें। मैंने कहा कि यह फ़ैसला सरकार लेगी। बिना कोई आधिकारिक राज़ बताए, मेरे मन में यह विचार आया कि हमें बदले की कार्रवाई करनी चाहिए। चिदंबरम ने आतंकवादी हमले के बाद सरकार के भीतर हुई चर्चाओं के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के साथ संभावित जवाबी कार्रवाई पर चर्चा की थी। उन्होंने याद करते हुए कहा, जब हमला हो रहा था, तब भी प्रधानमंत्री ने इस पर चर्चा की थी... और निष्कर्ष

यह था कि, जो काफी हद तक विदेश मंत्रालय और आईएफएस से प्रभावित था, हमें स्थिति पर शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। उन्होंने याद करते हुए कहा, मुझे प्रधानमंत्री का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि (तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा) मुझे गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। मैं वित्त मंत्रालय नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि मैं पाँच बजट पेश कर चुका था और एक साल में चुनाव होने वाले थे। हालांकि, चिदंबरम की इस स्वीकारोक्ति को भाजपा में कोई समर्थन नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि देश पहले से ही जानता है कि मुंबई हमलों को विदेशी ताकतों के दबाव के कारण गलत तरीके से संभाला गया था।

भाजपा अक्सर 2008 के मुंबई हमलों पर भारत की प्रतिक्रिया को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कमज़ोर रवैये का सबूत बताती रही है। इसके विपरीत, पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल में की गई ज्यादा आक्रामक कार्रवाइयों को रेखांकित करती है, जिनमें उरी हमले के बाद 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 2025 में शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर शामिल है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि मुंबई हमलों के बाद चिदंबरम शुरू में गृह मंत्री का पदभार संभालने के लिए अनिच्छुक थे, वे पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई चाहते थे, लेकिन दूसरों ने दबदबा बनाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इन टिप्पणियों को चिंताजनक बताया और कहा- इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान के साथ व्यवहार को लेकर उनकी क्या राय थी। 26/11 के हमलों के ठीक नौ महीने बाद, जुलाई 2009 में, मिस्र के शर्म अल-शेख, जो एक तटस्थ स्थान है, में पाकिस्तान के साथ एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह दुखद और आश्चर्यजनक दोनों है कि इस संयुक्त घोषणापत्र में बलूचिस्तान का उल्लेख किया गया था। इसका मतलब है कि, एक तरह से, वे उस झूठ को भी स्वीकार करने के लिए तैयार थे।

ठंडे रेगिस्तान में आग किसने भड़काई ?

विजय दर्डा

ऐसा माना जाता है कि फिल्म थ्री इडियट के मुख्य किरदार फुनसुख वांगडू की जो भूमिका आमिर खान ने निभाई थी, वह लेह-लद्दाख के पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की जिंदगी पर आधारित थी। लोग उन्हें जानते थे लेकिन फिल्म के साथ वे पूरे भारत के दिल में बस गए। विडंबना देखिए कि अब लेह में हुई हिंसा के साथ कई आरोपों से वे घिर गए हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है।

सवाल ये है कि क्या वांगचुक वाकई जिम्मेदार हैं या कुछ और छिपी ताकतें हैं जो सरहद पर भारत को कमजोर करने की साजिश रच रही हैं? लेह में हुई हिंसा में अब तक चार लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। हिंसा के कारणों को समझने से पहले यह समझिए कि मसला क्या है? लद्दाख इलाके का नाम है और लेह उसका प्रमुख शहर है। लद्दाख पहले जम्मू-कश्मीर राय का हिस्सा था। मगर वहां के लोग खुद को हमेशा उपेक्षित महसूस करते थे। आजादी के कुछ ही साल बाद लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष छेवांग रिग्जिन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखा था कि लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि यह इलाका धर्म, नस्ल, भाषा और संस्कृति के आधार पर कश्मीर से बिल्कुल अलग है। लद्दाख के ही एक प्रभावशाली नेता लामा कुशक बाकुला ने तो शेख अब्दुल्ला से नाराज होकर यहां तक धमकी दे दी थी कि यदि लद्दाख की मांगें नहीं मानी गईं तो तिब्बत के साथ जाने की भी सोच सकते हैं। वह केवल धमकी थी लेकिन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहा। साल 1979 में जब लद्दाख क्षेत्र का दो जिलों में परिसीमन किया गया तब मुस्लिम बहुल आबादी के कारण कारगिल को एक अलग जिला बनाया गया और बौद्ध बहुल आबादी के कारण लेह को अलग लेकिन इसके बाद लद्दाख के बौद्धों ने आरोप लगाने शुरू किए कि जम्मू-कश्मीर राय बौद्धों के मुकाबले मुस्लिमों के प्रति सहानुभूति रखता है। इसी असंतोष के कारण 1989 में हुए आंदोलन में तीन लोगों की जान चली गई थी। अंततः 2019 में जब जम्मू-कश्मीर राय का पुनर्गठन हुआ और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना तो इस पूरे इलाके में खुशियां छा गई थीं। हर ओर जश्न मनाया जा रहा था।

स्वयं वांगचुक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले दिल से प्रशंसा की। इसीलिए यह सवाल पैदा होता है कि जो इलाका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वजूद में आकर जश्न मना रहा था, वहां कुछ ही वर्षों में राय का दर्जा प्राप्त करने और छठी अनुसूची में शामिल होने की भूख कहां से जाग गई? यादातर लोगों को तो शायद यही पता नहीं होगा कि छठी अनुसूची आखिर है क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छठी अनुसूची चार पूर्वोत्तर रायों- असम, मेघालय, मिजोरम, और त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों के लिए एक प्रशासनिक प्रावधान है जिसका मकसद वहां की संस्कृति, जमीन व अन्य संसाधनों की रक्षा करना है। निश्चित ही लेह की संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, संसाधनों पर मूल अधिकार वहीं के लोगों का होना चाहिए मगर इसके लिए हिंसा तो सर्वथा अनुचित है। लद्दाख के लोग बहुत भोले हैं। मैं कई बार वहां गया हूं। पिछली बार जब कारगिल में सेना के जवानों के लिए लोकमत की ओर से निर्मित गर्म घरों का शुभारंभ करने मैं और मेरे अनुज राजेंद्र वहां गए थे तब हम जाते और आते समय कुछ देर के लिए लेह में रुके थे। रास्ते में रुक कर वहां के लोगों से बातचीत भी की थी। दिसंबर-जनवरी में तो तापमान शून्य से दस डिग्री से भी यादा नीचे गिर जाता है। ठंडा रेगिस्तान कहे जाने वाले इस इलाके में जीवन बहुत कठिन है। यहां के लोग शांति प्रिय हैं। वे अपने इलाके की संस्कृति को सहेजने के प्रति बेहद जागरूक हैं। आपको आश्चर्य होगा कि लद्दाख में पॉलीथिन पर सामाजिक प्रतिबंध के पचास साल से यादा हो गए। ऐसे इलाके के लोग अगर हिंसा पर उतारू हो जाएं तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। सामान्य तौर पर लोगों का कहना है कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 10 सितंबर को 35 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके समर्थन में लेह अपेक्स बॉडी (एलएबी) की युवा शाखा ने लेह बंद का आह्वान किया। सब कुछ ठीक-ठाक था। लेह का पूरा बाजार बंद था लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने भाजपा कार्यालय पर पत्थर फेंके। परिसर की एक इमारत को आग लगा दी और कुछ वाहन भी फूंक दिए। उसके बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने उपद्रवियों को काबू में करने की कोशिश की, गोलियां चलीं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और काफी लोग घायल हुए। इस स्थिति से आहत सोनम वांगचुक ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। उन्होंने बस इतना कहा कि युवा हताश हैं लेकिन हिंसा नहीं करनी चाहिए। पुलिस ने हिंसा को लेकर लेह के कांग्रेस पार्षद फुंटसोग स्टेनजिंग त्सेपाग के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, सोनम वांगचुक की संस्था पर भी नकेल कसी जा रही है। उनकी संस्था विदेशों से धनराशि नहीं ले पाएगी। मगर एक सवाल अनुत्तरित है कि सोनम वांगचुक या कोई भी ऐसी हिंसा को बढ़ावा क्यों देगा जब लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार की लगातार बातचीत हो रही है। छह अक्तूबर को फिर एक वार्ता निर्धारित है जिसमें एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी शामिल होने वाली है। हिंसा से तो लद्दाख को अलग राय का दर्जा दिए जाने की मांग कमजोर ही होगी। सीधा सा अर्थ है कि किसी ने युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की है। वो कौन है? क्या वो अपने भीतर से है या कहीं कोई बाहरी शक्ति तो इसमें शामिल नहीं है? जवाब तलाशना बहुत जरूरी है क्योंकि लद्दाख चीन की सरहद के पास है और वहां कोई भी आंतरिक कमजोरी हमारे लिए उतनी ही घातक हो सकती है जितनी कि कश्मीर घाटी में साबित हो रही है। मेरा मानना है कि हमें लद्दाख के लोगों की भावनाओं को सम्मान देना होगा और यह भी समझना पड़ेगा कि सोनम वांगचुक कोई राष्ट्रविरोधी व्यक्ति नहीं हैं। वे लद्दाख को उसके मूल स्वरूप में जिंदा रखना चाहते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि दुनिया की बहुत सी ताकतें भारत के खिलाफ खड़ी हैं क्योंकि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत उन्हें सुहा नहीं रही है। हम गलती से भी ऐसा कुछ न करें कि उन ताकतों के हाथ में हमारे हथियार आ जाएं।

सम्पादकीय...

भारत की विजय

भारत-पाकिस्तान के बीच गत रात्रि दुबई में हुए टी-20 क्रिकेट में जिन रोमांचक परिस्थितियों में भारत ने यह मैच पांच विकेट से जीता उससे भारतीय खिलाड़ियों के खेल कौशल का पता चलता है परन्तु इसे लेकर भारत के भीतर जो राजनीति हो रही है उसे हम गंभीरता से नहीं ले सकते हैं। क्रिकेट भी निश्चित रूप से एक खेल है और किसी खेल में जब दो टीमें खेलती हैं तो उनमें से एक हारती या जीतती है। जीतती वही टीम है जिसमें खेल कौशल अद्भुत होता है। क्रिकेट के साथ कोई भी अन्य टीम स्पर्धात्मक खेल केवल टीम भावना से ही जीता जा सकता है। भारत के गेंदबाजों व बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के मुकाबले हर मुकाम पर बेहतर प्रदर्शन किया अतः उसकी टीम विजयी रही। निश्चित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में किसी भी देश का सम्मान दांव पर रहता है। विशेषकर जब किसी भी खेल प्रतियोगिता में भारत व पाकिस्तान भिड़ते हैं तो आम भारतीय की रुची इसमें बहुत बढ़ जाती है। इसकी वजह केवल यही नहीं है कि पाकिस्तान का जन्म भारत से टूट कर 1947 में हुआ, बल्कि इसके पीछे मूल कारण पाकिस्तान का भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया है। अपने जन्म से लेकर आज तक पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन मानता आया है जबकि भारत का नजरिया ऐसा कभी नहीं रहा और इसने हमेशा कहा कि एक स्थिर और शान्त पाकिस्तान इस भारतीय उपमहाद्वीप के हित में है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान अपनी गुरबत की समस्या का हल इस क्षेत्र में शान्ति रख कर करे मगर उसने जो रास्ता चुना वह दहशतगर्दी और बद इन्तजामी का है जिससे पाकिस्तान आज बुरी तरह त्रस्त है। जहां तक खेलों का सवाल है तो पहले हाकी मैचों में हमें यह देखने को मिलता था। आजादी के पहले से ही भारत हाकी का विश्व चैम्पियन था। मगर 1960 में पहली बार ओलम्पिक खेलों में भारत को पाकिस्तान ने हराकर स्वर्ण पदक जीता था और भारत के हिस्से में रजत पदक आया था। इसके बाद से भारत हाकी के खेल में अपना दबदबा कायम रखने में कभी सफल रहा और कभी असफल। भारत-पाकिस्तान के बीच तीन युद्ध हुए मगर खेलों की अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में दोनों देशों की टीमें भाग लेती रहीं और एक-दूसरे के खिलाफ खेलती भी रहीं। मगर विगत अप्रैल महीने में जम्मू-कश्मीर राय के पहलगाम शहर के निकट पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जिस तरह 26 भारतीय पर्यटकों को उनका मजहब पूछ-पूछकर हलाक किया उससे पूरा देश गुस्से में था और पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने के हक में था। इसका जवाब भारत ने मई महीने में सैनिक आपरेशन सिन्दूर चला कर किया और पाकिस्तान के लगभग एक दर्जन सैनिक अड्डों को तबाह कर डाला। भारत सरकार कह रही है कि यह आपरेशन सिन्दूर पूरी तरह बन्द नहीं हुआ है और अभी भी चालू है। इस आपरेशन के चलते जब क्रिकेट के एशिया कप टूर्नामेंट के शुरू होने की बात सामने आयी तो भारत के अधिकतम लोगों ने राय व्यक्त की कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए और उसका बहिष्कार करना चाहिए परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ का सदस्य होने की वजह से भारत का ऐसा करना मुमकिन नहीं हुआ और उसने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच खेले। कुछ विपक्षी दल दलील दे रहे थे, विशेष कर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे शिव सेना कि भारत उस पाकिस्तान के खिलाफ किस प्रकार क्रिकेट मैच खेल सकता है जिसके आतंकवादियों ने 26 निरीह भारतीय नागरिकों का कत्ल किया हो? और जिसके खिलाफ आपरेशन सिन्दूर अभी तक चालू हो। यह दलील भारत के कुछ लोगों को तर्क संगत भी लगी और उन्होंने इसका खुलकर समर्थन भी किया परन्तु एक जिम्मेदार राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के तौर पर भारत के खिलाड़ियों ने एशिया कप में भाग लेना उचित समझा। ऐसा करके उन्होंने भारत के सम्मान पर कोई चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि अपने क्रिकेट कौशल पर भरोसा ही जताया। इस फैसले का बेहतर परिणाम निकला क्योंकि भारत की टीम ने एशिया कप जीत लिया। मगर भारतीय खिलाड़ियों ने जीती हुई एशिया कप ट्राफी किसी पाकिस्तानी के हाथ से लेनी गंवारा नहीं की और उन्होंने यह ट्राफी स्वीकार नहीं की। यह ट्राफी मैच खत्म होने पर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ली जानी थी। मोहसिन पाकिस्तान की सरकार में मन्त्री हैं। भारत की टीम ने अपने विजय समारोह में हिस्सा तो लिया मगर ट्राफी मोहसिन के हाथों से लेना स्वीकार नहीं किया। नकवी खेल मैदान में पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने से पहले ही एक तरफ खड़े हो गये थे। भारतीय खिलाड़ी अपना विजयोत्सव मनाने मैदान में उससे कुछ दूरी पर खड़े हो गये। उन्होंने अपने स्थान से हटने से यह कहकर इन्कार कर दिया कि वे जहां खड़े हैं वहीं ठीक जगह है। समारोह में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे समारोह में थोड़ा विलम्ब तो हुआ मगर व्यवधान नहीं। इस दौरान ट्राफी ड्रेसिंग रूम के अन्दर ले जाई गई। मगर मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम ड्रेसिंग रूम में चली गयी थी। मैच खत्म होने के लगभग 55 मिनट तक यह टीम रूम से बाहर ही नहीं निकली। जबकि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी अकेले खड़े हुए थे। पाकिस्तानी टीम की इस देरी की वजह से समारोह देर से शुरू हुआ और जब ट्राफी देने का समय आया तो भारतीय टीम ने इसे लेने से इन्कार कर दिया। अतः बहुत स्पष्ट है कि भारतीय टीम ने विजयी होकर भी भारत के गौरव के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया और एक पाकिस्तानी के हाथों ट्राफी लेने से इन्कार कर दिया। मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जिस प्रकार की मुद्राओं का प्रदर्शन किया वह भी खेल भावना के विरुद्ध ही रहा। इसलिए भारत को राजनीति छोड़कर अपनी क्रिकेट विजय पर गर्व होना चाहिए।

वैश्विक परिदृश्य में धमक बढ़ाता भारत

भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है। 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बनने की दिशा में अग्रसर है, जिसके पीछे इसकी लगातार आर्थिक वृद्धि और युवा कार्यबल की भूमिका है। भारत की 28.2 वर्ष की माध्य आयु इसे नवाचार और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण लाभ देती है, जो वैश्विक प्रभाव बढ़ाने में मददगार है। भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत का महत्व अत्यधिक है। एशिया के संगम स्थल पर स्थित भारत, हिंद महासागर में प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखता है और क्वाड, शंघाई सहयोग संगठन, एससीओ, ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों में अपनी सक्रिय भागीदारी से वैश्विक शासन संरचना में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा, भारत के पास चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सक्रिय सैन्य बल है, जो उसे रणनीतिक स्वायत्तता व सामरिक ताकत प्रदान करता है। वहीं भारत की वैश्विक पहचान उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, तीन करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीयों की शक्ति और योग, फिल्म उद्योग जैसे सॉफ्ट पावर उपकरणों के माध्यम से भी मजबूत हो रही है। इसके साथ ही भारत तकनीकी नवाचार, डेटा गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक गुड्स जैसे क्षेत्रों में भी वैश्विक नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। हालांकि भारत को रणनीतिक स्पष्टता और संस्थागत क्षमता बढ़ाने की चुनौतियों का सामना भी है, साथ ही विकास की असमानताएँ राष्ट्रीय एकता और वैश्विक भूमिका पर असर डालती हैं। फिर भी, भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ संतुलित साझेदारी तेरह करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीयों की शक्ति और योग,फिल्म उद्योग जैसे सॉफ्ट पावर उपकरणों के माध्यम से भी मजबूत हो रही है। इसके साथ ही भारत तकनीकी नवाचार, डेटा गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक गुड्स जैसे क्षेत्रों में भी वैश्विक नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। हालांकि भारत को रणनीतिक स्पष्टता और संस्थागत क्षमता बढ़ाने की चुनौतियों का सामना भी है, साथ ही विकास की असमानताएँ राष्ट्रीय एकता और वैश्विक भूमिका पर असर डालती हैं। फिर भी, भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ संतुलित साझेदारी स्थापित कर अपनी वैश्विक महाशक्ति बनने की यात्रा पर लगातार अग्रसर है। भारत की वैश्विक प्रभावशीलता तकनीकी प्रगति, कूटनीति और सांस्कृतिक शक्ति के क्षेत्र में निरंतर बढ़ रही है। इस प्रकार, भारत न केवल आर्थिक और सैन्य रूप से बल्कि कूटनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी दृष्टिकोण में भी एक समेकित वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, जो आने वाले दशकों में विश्व राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दे सकता है। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश होने के कारण कई सुरक्षा और सामरिक चुनौतियों का सामना करता है। प्रमुख चुनौतियाँ हैंजैसे सीमा विवाद: भारत के विभिन्न पड़ोसी देशों जैसे चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर विवाद और तनाव लगातार बना रहता है, जिससे सैन्य संघर्ष की संभावना रहती है।

आतंकवाद और उग्रवाद: जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व, और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में आतंकवादी और नक्सलवादी विद्रोह सक्रिय हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। साइबर सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयारी करनी होगी। तकनीकी विस्फोट के कारण साइबर हमलों में वृद्धि हुई है, जो सरकारी, सैन्य और नागरिक अवसंरचना को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं संगठित अपराध और तस्करी अवैध हथियार, मादक पदार्थों की तस्करी, और द्वेषपूर्ण समूहों की गतिविधियाँ देश की समग्र सुरक्षा को चुनौतियाँ देती हैं। खुफिया और सुरक्षा एजेंसिओं की क्षमता और समन्वय के लिए और काम करने की जरूरत हैसुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसिओं के बीच बेहतर समन्वय और आधुनिक तकनीक के उपयोग की आवश्यकता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत को अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल प्रणाली और निगरानी तकनीकों का विकास और तैनाती जरूरी है ताकि सीमा और आंतरिक खतरों से त्वरित और प्रभावी निपटारा हो सके। केंद्र और रायों के बीच सूचनाओं का तालमेल बढ़ाना और विशेष तकनीकी खुफिया इकाइयों का गठन आवश्यक है। स्थानीय लोगों को सुरक्षा व्यवस्था में शामिल करना और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखना महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा कड़े कानून और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना होगा, साथ ही हर विभाग में साइबर सुरक्षा सेल बनाना जरूरी है। ड्रोन, सेंसर्स और बॉर्डर फेंसिंग के माध्यम से अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और सतत निगरानी करनी होगी। आतंकवाद निरोधक कानूनों को मजबूती देना, नक्सलियों से बातचीत व विकासकारी योजनाओं से उग्रवाद को जड़ से खत्म करना महत्वपूर्ण है। भारत की सुरक्षा के लिए समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का निर्माण और निरंतर सुधार भी अत्यंत आवश्यक है, जिसमें सभी सुरक्षा बल, खुफिया एजेंसियाँ, और नागरिक सामूहिक रूप से मिल कर काम करें। इस तरह भारत अपनी बढ़ती वैश्विक भूमिका के साथ सुरक्षा और सामरिक बल भी मजबूत कर सकता है। यह रणनीतियाँ भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को समेकित रूप से मजबूत कर सकती हैं और देश को स्थिरता, सुरक्षा एवं विकास की दिशा में अग्रसर बनाएंगी।

हालांकि भारत की स्थिति आज पूर्व की अपेक्षा काफी मजबूत हो चुकी है अब भारत की स्थिति वैश्विक परिदृश्य में ऐसी है की कोई भी वैश्विक निर्णय भारत की उपस्थिति के बिना लिया जाना असंभव है।

वैश्विक परिदृश्य में भारत केंद्र बिंदु बन चुका है। भारत की उपेक्षा या भारत के साथ टकराव करने की सोचना अब दुश्मन देश को भी मुश्किल लगने लगा है।

विदेशी फिल्मों पर 100फीसदी टैरिफ से बॉलीवुड होगा प्रभावित

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत समेत पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। अपने पारंपरिक अंदाज में सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा है कि अब अमेरिका के बाहर बनी किसी भी फिल्म पर 100फीसदी टैरिफ (कर) लगाया जाएगा। उनका तर्क है कि अमेरिकी फिल्म उद्योग को अन्य देशों ने चुरा लिया है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे से टॉफी छीन ली जाती है। देखा जाये तो यह फैसला केवल कूटनीतिक या वाणिज्यिक कदम नहीं है, बल्कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट सोच का नया नमूना है। किंतु सवाल यह है कि यह लगातार भारत जैसे देशों के हितों के विरुद्ध क्यों जाता है? और इससे भारत की सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक धारा यानि बॉलीवुड पर क्या असर पड़ेगा? हम आपको बता दें कि ट्रंप का राजनीतिक आधार अमेरिकी मध्यवर्ग और घरेलू उद्योग जगत है, जो मानता है कि वैश्वीकरण ने उनकी नौकरियाँ छीन लीं। यही सोच फिल्म उद्योग में भी दिखाई देती है। अमेरिकी स्टूडियो लंबे समय से VFX और एनीमेशन का बड़ा हिस्सा भारत जैसे देशों में आउटसोर्स करते रहे हैं। यह भारत के लिए रोजगार और तकनीकी विकास का बड़ा अवसर था। लेकिन ट्रंप इसे अमेरिका की कमजोरी के रूप में देखते हैं। देखा जाये तो भारत के हितों के विरुद्ध ट्रंप की नीति कोई नई बात नहीं है। पहले भी उन्होंने स्टील, एल्युमिनियम और आईटी सेवाओं पर कठोर रुख अपनाया। अब फिल्म उद्योग को निशाना बनाकर वह भारत को दोहरा नुकसान पहुँचा रहे हैं। ट्रंप के फैसले के बॉलीवुड पर संभावित असर की बात करें तो आपको बता दें कि भारतीय फिल्म उद्योग हर साल 100 से 150 मिलियन डॉलर अमेरिकी बाजार से कमाता है। हिंदी और तेलुगु की बड़ी फिल्में अकेले 10 मिलियन डॉलर तक की कमाई अमेरिका में करती हैं। यदि 100फीसदी टैरिफ लागू होता है तो वहाँ टिकट की कीमत दोगुनी होकर 40 डॉलर तक पहुँच सकती है। इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे भारतीय प्रवासी दर्शक, जो अब तक भारतीय फिल्मों को बड़े पैमाने पर समर्थन देते आए हैं। इसके अलावा, OTT और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे- नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, डिज्नी+ हॉटस्टार के लिए भी यह झटका है। अगर भारतीय कंटेंट महंगा होगा, तो उसकी पहुँच कम होगी और प्रोड्यूसर्स को घाटा उठाना पड़ेगा। इससे भारतीय सिनेमा का वैश्विक प्रसार धीमा हो सकता है। विडंबना यह है कि ट्रंप जिस हॉलीवुड की रक्षा करना चाहते हैं, उसी को उनके फैसले से सबसे बड़ा नुकसान होगा। हम आपको बता दें कि अमेरिकी फ़िल्म उद्योग की 70फीसदी कमाई अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से होती है। यदि अन्य देश जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो हॉलीवुड का कारोबार ध्वस्त हो सकता है। इसके अलावा, हॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्में- अवेंजर्स: एंडगेम, ड्यून, जंगल बुक, इंटरस्टेलर का पोस्ट-प्रोडक्शन भारत जैसे देशों में हुआ है। अगर यह सहयोग बाधित होता है तो न केवल लागत बढ़ेगी, बल्कि रचनात्मक गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।

स्वदेशी यानी अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ना

भारत एक त्यौहारों का देश है, हर महीने कोई न कोई त्यौहार होता है। लोग त्यौहार पर जमकर खरीदारी करते हैं, इस खरीदारी का असर देश की इकोनॉमी पर भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अवसरों पर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया है, ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने लोगों से स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने का आग्रह किया है। पीएम मोदी लगातार स्वदेशी को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। अभी सामने दिवाली है, आप यहीं से बदलाव की शुरूआत कर सकते हैं। पीएम मोदी ने 'वोकल फॉर लोकल' को खरीदारी का मंत्र बनाने का आग्रह किया। उनका कहना है कि हमें हमेशा उन्हीं चीजों को खरीदना चाहिए जो देश में बनी हों और देश के लोगों ने बनाई हों। उन्होंने स्वदेशी की अपनी परिभाषा भी स्पष्ट की, जिसमें कहा गया कि उत्पादन में लगा पसीना मेरे देशवासियों का है। वास्तव में, स्वदेशी वस्तुएं केवल उत्पाद ही नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, धरोहर और हमारे मान-सम्मान का प्रतीक हैं।

बीती 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुडा से एक ऐतिहासिक पहल करते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की पूरी तरह स्वदेशी 4जी सेवा को देशभर में लॉन्च किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा संकल्प है चिप से लेकर शिप तक, हर चीज में भारत आत्मनिर्भर बने। बीती 28 सितंबर को अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता स्वदेशी उत्पादों से ही होकर गुजरता है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से आगामी त्यौहारों को स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने और वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से देश में उत्पादित उत्पाद खरीदने का संकल्प लेने का आह्वान किया। बीती 21 सितंबर को, पीएम मोदी ने भारतीयों से गर्व से कहने के लिए कहा, मैं स्वदेशी खरीदता हूं। उन्होंने कहा कि हर घर और दुकान को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनना चाहिए। स्वदेशी को प्राथमिकता देने से स्थानीय कारीगरों और उद्योगों का समर्थन,आर्थिक विकास को बढ़ावा, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम, गुणवत्ता और विश्वसनीयता का लाभ मिलता है। स्वदेशी अपनाना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। हर त्यौहार पर बाजार में स्वदेशी और विदेशी सामान होते हैं, अधिकतर लोग सस्ते के चक्कर में विदेशी सामान खरीद लेते हैं। हालांकि अधिकतर मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक्स सामान अभी भी भारत में असेंबल होकर बिकता है, ऐसे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया कैटेगरी में आते हैं। धार्मिक भावनाओं से जुड़े होने के कारण मूर्तियों का चीनी आयात व्यापक विरोध का विषय रहा है। दावा किया जा रहा है कि मूर्तियों में चीनी हिस्सेदारी 70-80 फीसदी से घटकर 10 फीसदी रह गई लेकिन अभी भी लक्ष्मी-गणेश की चाइनीज मूर्तियां खूब बिकती हैं, खरीदार आप-हम जैसे लोग ही हैं। दिवाली और बाकी त्यौहारों पर चाइनीज झालर खूब बिकती है, क्योंकि ये सस्ती होती है लेकिन इसकी क्वालिटी बेहद खराब होती है। व्यापार संगठन कैट ने 500 से यादा चीनी सामानों की बहिष्कार सूची में इसे भी रखा है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2024 में दिवाली पर सजावटी सामानों जैसे एलईडी झालर, लाइट्स और गिफ्ट आइटम्स का चीन से आयात करीब 10,000-15,000 करोड़ रुपये का रहा था। कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स ने 2024 की दिवाली पर लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपये का खुदरा कारोबार होने का अनुमान लगाया था।

यह पिछले त्यौहारी सीजन के मुकाबले एक रिकॉर्ड कारोबार था, क्योंकि लोगों ने चीनी सामानों की जगह भारतीय सामानों को प्राथमिकता दी। कुछ शुरुआती अनुमानों के अनुसार, 2025 में दिवाली के दौरान ई-कॉमर्स और ऑफलाइन दोनों तरह के खुदरा कारोबार में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण स्वदेशी की भावना का संचार, जीएसटी दरों में कटौती और अन्य धार्मिक और सामाजिक कारण भी शामिल हैं। रिसर्च फर्म रेडसीर के अनुमान के मुताबिक, 2025 में त्यौहारी ई-कॉमर्स बिक्री 1.15 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकती है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 20-25 फीसदी की वृद्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी दरों में कटौती से बाजार में ग्राहकों का उत्साह बढ़ा है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक सुधार से जुड़े कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब भारत एक विकसित राष्ट्र कहलाएगा। विकसित राष्ट्र बनाने में हर एक भारतीय का योगदान होगा। हर किसी को अपने स्तर पर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। इस बीच भारत की तरक्की को कई देश पचा नहीं पा रहे हैं, भारत को रोकने के लिए साजिशें रची जा रही है लेकिन यह नए दौर का भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। ऐसे में जब 140 करोड़ लोग मिलकर देश को संवारने का काम करेंगे तो विदेशी ताकतें भी टिक नहीं पाएंगी। 22 सितंबर से देश जीएसटी रिफॉर्म लागू हो गया है जो कि आर्थिक तौर पर एक बड़ा कदम है। दिनचर्या की 90 फीसदी से यादा चीजें के दामों पर इसका सीधा असर अब दिखाई देने लगा है। त्यौहारों पर स्वदेशी वस्तुएं कैसे चुनें यह अहम सवाल है। नवरात्रि और दिवाली जैसे त्यौहारों के लिए, चीनी उत्पादों के बजाय मिट्टी के दीये, हस्तनिर्मित सजावटी सामान और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए अन्य सजावटी सामान खरीदने को प्राथमिकता देनी होगी, वहीं अपने प्रियजनों को उपहार देने के लिए, भारतीय हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाकृति और स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को चुनें। त्यौहारों के लिए खादी और हैंडलूम जैसे स्वदेशी कपड़ों को प्राथमिकता दें जो भारतीय बुनाई और वस्त्र कला को दर्शाते हैं, वहीं सबसे खास बात मिठाई, नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों के लिए स्थानीय मिठाई की दुकानों और उत्पादकों का समर्थन करें।

भारत एक श्रम आधारित अर्थव्यवस्था है। हमारे युवा पूरे विश्व में अपनी स्किल्स के लिए पहचान रखते हैं। आज समय आ गया है कि हम स्वदेशी उत्पादों को अधिक से अधिक अपनाएं और बढ़ावा दें। अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। त्यौहारों के समय स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देना, 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे अभियानों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है।

यह न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि जब हम भारतीय उत्पाद खरीदते हैं तो छोटे और बड़े व्यवसायों को मदद मिलती है, नौकरियों के अवसर बढ़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा राष्ट्र स्वदेशी के प्रति वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है। हमारी संस्कृति ही हमें स्वदेशी का भाव सिखाती है। हम देशी वस्तुओं के प्रति अपने अंतर्मन से जुड़े हुए हैं। यह भावना ही स्वदेशी उत्पादों को और बेहतर स्वरूप देने की प्रेरणा देती है। स्वदेशी का अर्थ दुनिया से अलग-थलग होना नहीं है, बल्कि एक मजबूत और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ना है। यह देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है।

अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। त्यौहारों के समय स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देना, 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे अभियानों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि जब हम भारतीय उत्पाद खरीदते हैं तो छोटे और बड़े व्यवसायों को मदद मिलती है, नौकरियों के अवसर बढ़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा राष्ट्र स्वदेशी के प्रति वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है। हमारी संस्कृति ही हमें स्वदेशी का भाव सिखाती है। हम देशी वस्तुओं के प्रति अपने अंतर्मन से जुड़े हुए हैं। यह भावना ही स्वदेशी उत्पादों को और बेहतर स्वरूप देने की प्रेरणा देती है। स्वदेशी का अर्थ दुनिया से अलग-थलग होना नहीं है, बल्कि एक मजबूत और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ना है। यह देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने करना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साथ पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582083548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2017/00083)

बिहटा-अनुग्रह नारायण रोड नई रेल लाईन का काम होगा चालू, 3606 करोड़ रुपये स्वीकृत

गोरखपुर।

पटना, अरवल, जहानाबाद एवं औरंगाबाद जिले के लाखों लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने बिहटा-अनुग्रह नारायण रोड नई लाइन का निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से चालू करने का फैसला लिया है। इसके लिए राशि की स्वीकृति दे दी गई है और पूर्व मध्य रेल को निर्देश दिया गया है कि परियोजना के लिए समेकित तरीके से कार्य को प्रारंभ किया जाए। सूत्रों के अनुसार इस परियोजना से मगध एवं शाहाबाद क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। परियोजना से संबंधित विस्तृत विवरण तैयार कर दिया गया है जिसके अनुसार इस परियोजना के निर्माण पर कुल लागत रुपये 3606.42 करोड़ की लागत आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परियोजना पर काम चालू करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। 117 किमी लंबी इस रेल लाइन से बिहटा-अनुग्रह नारायण रोड के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। यहां ध्यान देने बात यह है कि अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद के बीच लगभग 13 किमी लंबी रेल लाइन को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है और इस पर कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर, पटना से अरवल, औरंगाबाद की सीधा रेल संपर्क स्थापित हो जाएगा और इस क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होगी। बिहटा में आरओआर को इस परियोजना के तहत स्वीकृति मिली है जिससे निर्बाध तरीके से इस प्रस्तावित लाइन पर यातायात सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इस परियोजना के पूर्ण होने से एक ओर जहां इस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर डीडीयू-पटना-झाझा मेन लाइन और डीडीयू-गया-कोडरमा ग्रैंड कॉर्ड लाइन के मध्य एक और नया वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा।

समाज और शैक्षणिक संस्थानों का आपसी सहयोग ही प्रगति का आधार : प्रो. राकेश यादव

जौनपुर।

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर एवं कुलपति प्रो. वन्दना सिंह के संरक्षकत्व में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत विश्वविद्यालय के एनएसएस प्रकोष्ठ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र, सुल्तानपुर, करंजाकला का भ्रमण एवं विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को कॉपी, कलम किताब ,पेंसिल, बिस्कुट, टाफी आदि शिक्षण एवं खाद्य सामग्री वितरित की गई। साथ ही साथ जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित उपयोगी जानकारियां प्रदान की गईं। बच्चों को पौष्टिक आहार एवं स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया। कार्यक्रम

आंगनबाड़ी केंद्र सुल्तानपुर में शिक्षण एवं पोषण सामग्री वितरित

संयोजक डॉ. राज बहादुर यादव ने कहा कि सेवा पखवाड़ा समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम है और इस प्रकार के कार्यक्रमों से जमीनी स्तर पर जनजागरूकता बढ़ती है। गाँव गोद कार्यक्रम के समन्वयक प्रो. राकेश कुमार यादव ने अपने उद्बोधन में ग्राम विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि समाज और शैक्षणिक संस्थानों का आपसी सहयोग ही प्रगति का आधार है। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामवासियों एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की और सेवा पखवाड़े को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री मंजू देवी, सहायक अध्यापिका ज़ीनत शमीम, बबीता यादव अनीता यादव,संतोष कुमार, एवं समाजसेवी सर्वेश, संदीप आदि उपस्थिति रहे।

सेवा पखवाड़ा व मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सुरक्षा पर विशेष सत्र

देवरिया।

सेवा पखवाड़ा एवं मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत मंगलवार को महिला थाना एवं कोतवाली सलेमपुर में महिला सुरक्षा और कानून विषय पर एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को उनके संवैधानिक अधिकारों, विधिक प्रावधानों और आत्मरक्षा उपायों की जानकारी देना रहा।

इस मौके पर महिला कल्याण विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कानूनी विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों और प्रबुद्ध वर्ग ने सहभागिता की।

केंद्र प्रशासक नीतू भारती, मनोवैज्ञानिक मीनू जायसवाल एवं जेंडर स्पेशलिस्ट मंशा सिंह ने महिला उत्पीड़न निवारण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन

कानून की बारीकियों से कराया अवगत

उत्पीड़न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण और साइबर अपराधों से बचाव जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

पुलिस अधिकारियों ने प्रतिभागियों को 1090 वूमेन पावरलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन तथा आपातकालीन सेवा 112 जैसी सुरक्षा सेवाओं के संचालन व शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं से सतर्क रहने और बिना झिझक शिकायत दर्ज कराने की अपील भी की। सत्र के दौरान प्रतिभागी महिलाओं व प्रबुद्धजनों ने भी अपने विचार रखे और न्याय तक शीघ्र पहुँच तथा कानूनी सहयोग को और प्रभावी बनाने पर बल दिया।

तैराकी की मंडली प्रतियोगिता में जनपद कुशीनगर बालक वर्ग बना ओवरऑल चैंपियन

कुशीनगर।

अनिल कुमार मिश्र जिला व्यायाम शिक्षक कुशीनगर ने बताया कि तैराकी की मण्डली बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन जनपद देवरिया के स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम के तरण ताल में आयोजित की गई, जिसमें मंडल के चारों जनपदों ने प्रतिभाग किया। जनपद कुशीनगर ने तैराकी की प्रतियोगिता में बालक वर्ग में ओवर आल चैंपियन का खिताब जीता ,उसी क्रम में बालिका वर्ग में ओवरऑल उप विजेता रही। इसी क्रम में बालक वर्ग में रियाजुद्दीन 50मीटर,100मीटर बैक स्ट्रोक में प्रथम और और 200 मीटर फ्री स्टाइल में दूसरा स्थान अपूर्व 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 100 मी ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मी आईएम में प्रथम स्थान, धीरेंद्र चौहान 50 मीटर ,100 मीटर बटरफ्लाई और रिले में प्रथम, सुगम 50 मीटर फ्रीस्टाइल में द्वितीय और 100 मीटर फ्री स्टाइल में तृतीय , अनु 100 मी बेस्ट स्ट्रोक में प्रथम, रितिका 100 मीटर बटरफ्लाई में द्वितीय,200 मी फ्री स्टाइल में द्वितीय ,साधना 50 मीटर फ्रीस्टाइल में द्वितीय , 100मीटर फ्री स्टाइल में द्वितीय,अर्चना 50 मी बैक स्ट्रोक में द्वितीय,100 बैक स्ट्रोक में द्वितीय, चार घोड़े 50 मीटर रिले में बालक वर्ग प्रथम 4 * 50 मीटर रिले बालिका द्वितीय 100 मीटर बटरफ्लाई बालक प्रथम स्थान प्राप्त कर जनपद कुशीनगर का नाम रोशन किया इस उपलब्धि पर डॉ राम जियावन मौर्य जिला बेसिकशिक्षाअधिकारीकुशीनगर , अमितेश कुमार खंड शिक्षा अधिकारी हाटा, डॉ प्रभात चंद्र राय, रजनीश चंद्र द्विवेदी, अमित कुमार चौहान, रीता गुप्ता, जया रॉय, सुरेंद्र बहादुर सिंह, अशोक यादव,मुकेश नारायण मिश्रा, अखिलेश सिंह, सुधीर कुमार, नीरज बंका, सभी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी टीम प्रभारी के रूप में विजयपाल नारायण त्रिपाठी , टीम मैनेजर सुरेंद्र कुमार सिंह, भगवान नाथ तिवारी, टीम कोच बैजनाथ कनौजिया, उपेंद्र कुमार सिंह रहे।

दुर्गापूजा व दशहरे पर शहर में लागू होगा ट्रैफिक डायवर्जन, एसपी ने जारी किया आदेश

देवरिया। आगामी दुर्गापूजा शारदीय नवरात्र और दशहरे के मद्देनज़र देवरिया पुलिस प्रशासन ने शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने का निर्णय लिया है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर यह व्यवस्था मंगलवार की सुबह 8 बजे से प्रभावी हो होकर 8 अक्टूबर की सुबह 3 बजे तक लागू रहेगी। शहर में बढ़ती भीड़ और मूर्ति विसर्जन के दौरान होने वाली अव्यवस्था को रोकने के लिए प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगाने का फैसला किया है। आदेश के अनुसार ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, बड़ी बसें, मिक्सर वाहन, गैस सिलेंडर लदे वाहन और पेट्रोल-डीजल के टैंकर जैसे भारी वाहन निर्धारित मार्गों से ही गुज़र सकेंगे। प्रशासन ने अलग-अलग चौराहों और तिराहों पर वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की है, जिनके ज़रिए भारी वाहनों को शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। विशेष रूप से अष्टमी, नवमी और दशमी को सुरक्षा और सुगम यातायात को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का भारी व्यवसायिक वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इन तीनों दिनों में शहर क्षेत्र में 24 घंटे पूरी तरह नो-एंट्री लागू रहेगी। इसके अलावा अन्य दिनों में सुबह 3 बजे से 6 बजे तक ही आंशिक छूट दी जाएगी। एसपी संजीव सुमन ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और यातायात पुलिस के साथ सहयोग करें, ताकि दुर्गापूजा और दशहरा का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

दुमही में हिंदू-मुस्लिम पक्ष आमने-सामने, पुलिस ने संभाला हालात

तमकुही राज कुशीनगर।

- दुर्गा पूजा पांडाल के पास झड़प से गांव में तनाव फैल गया
- सीओ-एसओ ने फोर्स संग पहुंचकर स्थिति पर पाया काबू

सेवरही थानाक्षेत्र के ग्राम पंचायत दुमही में पंचायत भवन की चाबी को लेकर सोमवार की रात दो अलग-अलग संप्रदाय के युवकों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और दुर्गा पूजा पांडाल के पास अफरा-तफरी मच गई।

तनावपूर्ण माहौल के बीच मंगलवार की सुबह दोनों पक्षों के लोग फिर आमने-सामने आ गए। बहस बढ़ते ही दोबारा हाथापाई शुरू हो गई। मामला हिंदू-मुस्लिम पक्षों के बीच होने के कारण ग्रामीणों में सनसनी फैल गई और किसी ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर क्षेत्राधिकारी राकेश प्रताप सिंह और थानाध्यक्ष धीरेंद्र राय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को हटाकर हालात काबू में किए। गांव के बुद्धिजीवियों व जनप्रतिनिधियों की मदद से दोनों पक्षों को समझाया गया। कुछ युवकों को हिरासत में लेकर थाने भेजा गया। पुलिस की तत्परता से गांव में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने से बच गया। एसओ ने कहा कि धार्मिक आयोजन में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

भाजपा प्रवक्ता के बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

पडरौना, कुशीनगर।

केरल के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर असंवेदनशील और अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में आज पडरौना विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कठकुइया मोड़ स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टिप्पणी को लोकतांत्रिक मर्यादाओं और राजनीतिक शिष्टाचार पर गहरी चोट बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के महान नेताओं के प्रति लगातार अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रही है। यह प्रवृत्ति न केवल अस्वीकार्य है बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। विरोध प्रदर्शन में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मांग की कि भाजपा प्रवक्ता तुरंत सार्वजनिक माफी मांगे, और और गृह मंत्री राहुल गांधी के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। इस मौके पर मोहम्मद जहीरुद्दीन, जिला सचिव जाहिद कुरैशी आउट रिच जिला अध्यक्ष अनिल यादव, राजू कुमार भारती, मुस्लिम अंसारी (ब्लॉक अध्यक्ष, बिशनपुर), अरमान अली, सुरेंद्र सिंह, तौसीफ अहमद, सम्राट सिंह सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रक्षा मंत्री बोले- आज की चुनौतियों से निपटने के लिए साझा प्रणाली जरूरी, एकीकरण से बढ़ेगा आत्मविश्वास

नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि आज के समय में साइबर हमलों, सूचना युद्ध और बदलती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना के बीच बेहतर तालमेल और एक समान प्रणाली की जरूरत है। वह दिल्ली में आयोजित त्रि-सेवा संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय इस दिशा में हरसंभव सहयोग करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी सेनाओं ने वर्षों के अनुभव से अपनी ऑडिट प्रणाली विकसित की है। लेकिन आज के एकीकृत अभियानों के दौर में जरूरी है कि ये प्रणाली एक-दूसरे जुड़ी हों। अगर हर सेना अलग-अलग काम करेगी, तो फैसला लेना मुश्किल हो सकता है। एकीकृत प्रणाली से सेनाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज हमें साइबर हमलों और सूचना युद्ध का खतरा है, इसलिए हमें इनके लिए मानक तय करने होंगे। उन्होंने आगे कहा, जब हम मानक तय करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सेनाओं की अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। हम हर सेना पर एक जैसा तरीका नहीं थोप सकते। हमें ऐसी प्रणाली बनानी होगी जो तीनों सेनाओं के काम को एकसाथ जोड़े। मुझे भरोसा है कि इस पर गंभीर चर्चा होगी और रक्षा मंत्रालय पूरा सहयोग करेगा। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि देश को इस दिशा में लगातार काम करने की जरूरत है, ताकि एक ऐसी आधुनिक और सक्षम प्रणाली तैयार की जा सके जो सभी सेवाओं के लिए उपयोगी हो। उन्होंने कहा, इसके लिए हमें लगातार संवाद की जरूरत होगी। इस प्रक्रिया में नेतृत्व की भूमिका बहुत अहम होगी। हर कदम पर यह स्पष्ट करना होगा कि यह सुधार क्यों जरूरी है। जब तक हर सेवा और हर कर्मचारी को संयुक्तता का महत्व समझ में नहीं आएगा, तब तक यह सफल नहीं हो सकता। हम दूसरे देशों के अच्छे अनुभवों से सीख सकते हैं, लेकिन हर देश की अपनी परिस्थितियां होती हैं। हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से समाधान तैयार करना होगा। रक्षा मंत्री ने थल सेना, वायु सेना और नौसेना के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि देश ऑपरेशनल तैयारियों की दिशा में आगे बढ़ रहा है,

लेकिन अब अगला कदम त्रि-सेवा लॉजिस्टिक्स का एकीकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें एक ऐसी डिजिटल प्रणाली बनानी चाहिए जो हर सेवा की जरूरतों का सम्मान करे और सभी के लिए जरूरी संसाधनों की स्थिति को साझा रूप से दिखा सके। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। हमें मिलकर संयुक्तता की ओर बढ़ना है।

जब तीनों सेनाएं एक साथ आगे बढ़ेंगी, तभी हम बड़ी चुनौतियों का डटकर सामना कर सकेंगे राजनाथ सिंह ने देवी दुर्गा का उदाहरण देते हुए कहा, जब चुनौतियां बहुत बड़ी हों, तो एकता की ताकत अजेय बन जाती है। हमारी सेना ऑपरेशनल तैयारी कर रही है, वायुसेना और नौसेना भी इसी दिशा में काम कर रही है। लेकिन जैसे ही हम संयुक्त सेवा कमान की बात करते हैं, तो अगला कदम अखिल भारतीय त्रि-सेवा लॉजिस्टिक्स एकीकरण की दिशा में होना चाहिए।

बिहार में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी

चुनाव आयोग ने बिहार में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस बार वोटर लिस्ट में करीब 14 लाख से अधिक नए मतदाता भी शामिल हुए। इनमें अधिकतर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है।

पटना।

मतदाता सूची प्रारूप का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि आज यानी 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता इस लिंक पर क्लिक कर अपना नाम चेक कर सकते हैं। करीब सात करोड़ 30 लाख से अधिक मतदाताओं की फाइनल सूची जारी की गई। खास बात यह है कि इस बार वोटर लिस्ट में करीब 14 लाख से अधिक नए मतदाता भी शामिल हुए। इनमें अधिकतर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है। इधर, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को सार्वजनिक करने के साथ-साथ हर जिले के निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में भौतिक प्रति भी उपलब्ध करवा दी है। सभी राजनीतिक दलों को भी मतदाता सूची प्रारूप की अंतिम सूची उपलब्ध करवा दी गई।

65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए थे

निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य की शुरुआत जून माह में की थी। इस कार्य से पहले 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे। इसके पुनरीक्षण कार्य के बाद कुल 65 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे थे। इनमें 22 लाख से अधिक मृत मतदाता, करीब 35 लाख विस्थापित मतदाता थे। वहीं करीब सात लाख लोग ऐसे मतदाता थे, जिनका नाम दो जगह दर्ज था। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन्हें दावा आपत्ति के लिए 30 दिन का वक्त दिया था।

किन जिलों से कितने वोटरों का नाम हटा है

मतदाता पुनरीक्षण कार्य के बाद जो वोटर लिस्ट प्रकाशित किए गए हैं, उनमें सभी जिलों के हजारों लोगों के नाम कट गए हैं। इनमें पश्चिम चम्पारण से 191376, पूर्वी चम्पारण से 316793, शिवहर से 28166, सीतामढ़ी से 244962, मधुबनी से 352545, सुपौल से 128207, अररिया से 158072, किशनगंज से 145668, पूर्णिया से 273920, कटिहार से 184254, मधेपुरा से 98076, सहरसा से 131596, दरभंगा से 203315, मुजफ्फरपुर से 282845, गोपालगंज से 310363, सीवान से 221711, सारण से 273223, वैशाली से 225953, समस्तीपुर से 283955, बेगूसराय से 167756, खगड़िया से 79551, भागलपुर से 244612, बांका से 117346, मुंगेर से 74916, लखीसराय से 48824, शेखपुरा से 26256, नालंदा से 138505, पटना से 395500, भोजपुर से 190832, बक्सर से 87645, कैमूर (भभुआ) से 73940, रोहतास से 156148, अरवल से 30180, जहानाबाद से 53089, औरंगाबाद से 159980, गया से 245663, नवादा से 126450 और जमुई से 91882 मतदाताओं का नाम सूची प्रारूप में नहीं है।

बरेली में चला बुलडोजर, सील होगा हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों का अवैध बाजार

सपा पार्षद के चार्जिंग स्टेशन पर चला बुलडोजर, तौकीर के करीबी का बसातघर सील; रिश्तेदार हिरासत में

बरेली।

बरेली में बवाल की साजिश रचने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों और रिश्तेदारों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मंगलवार को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बानखाना मोहल्ले में बड़ी कार्रवाई की। यहां सपा पार्षद उमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि नाले पर बाउंड्रीवाल बनाकर अवैध तरीके से चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था। बुलडोजर से बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई से खलबली मच गई। मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार मोहसिन रजा खान और उसके भाई को हिरासत में लिया गया है। मोहसिन रजा मस्जानी मियां का दामाद है। मोहसिन के घर पर कार्रवाई करने के लिए बीडीए और नगर निगम की टीम पहुंची थी। इस दौरान मोहसिन रजा की अफसरों से तीखी नोकझोंक हो गई। मोहसिन ने अखिला भाजपा जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाया और कहा कि यह मामला सिर्फ राजनीतिक है। वह 2005 में आईएमसी छोड़ चुके हैं। तौकीर रजा से कोई वास्ता भी नहीं है। मोहसिन ने कहा कि तौकीर रजा से उसका कोई वास्ता नहीं है। यह सब भाजपा अखिला जिलाध्यक्ष के कहने पर हो रहा है। उन्होंने पहले भी उन पर गोकशी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मोहसिन के पिता ने कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाया तो टीम ने कार्रवाई रोकी। वहीं मोहसिन रजा और उसके भाई को हिरासत में ले लिया गया है। मोहसिन रजा के घर के सामने ही नाले पर अवैध चार्जिंग स्टेशन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। बीडीए की टीम ने शाहजहांपुर रोड स्थित नरियावल में हमसफर बसातघर को सील कर दिया है। ये बसातघर शराफत का है, जो शहर के सूफीटोला का निवासी है और मौलाना तौकीर रजा का बेहद करीबी बताया जाता है।

पहले पीड़ितों का दर्द सुनेंगे, फिर रिपोर्ट देंगे, करूर भगदड़ पर बोले अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु के करूर का दौरा करने वाला भाजपा-एनडीए नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पहले उन लोगों के विचार सुनेगा जिन्होंने भगदड़ में अपने परिजनों को खोया है, उसके बाद अधिकारियों से प्रतिक्रिया एकत्र करेगा और इस दुखद घटना के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। भाजपा-एनडीए प्रतिनिधिमंडल में शामिल ठाकुर ने एएनआई को बताया कि पहले हम उन लोगों के विचार सुनेंगे जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, स्थानीय लोगों और अधिकारियों से बात करेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे और फिर हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। करूर का दौरा करने वाले आठ सदस्यीय एनडीए-भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कोयंबटूर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल 27 सितंबर को भगदड़ की परिस्थितियों की जांच करेगा, प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेगा और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है, जिसमें भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, बैजयंत पांडा, अपराजिता सारंगी, रेखा शर्मा, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) से पुट्टा महेश कुमार शामिल हैं। भाजपा सांसद हेमा मालिनी इस समिति की संयोजक हैं। इस बीच, करूर सिटी पुलिस ने तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के करूर पश्चिम जिला सचिव मथियाझगन को पार्टी प्रमुख विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई, एडीजीपी डेविडसन देवासिरवथम ने एएनआई को बताया। पुलिस ने करूर शहर के पदाधिकारी पौल राज को भी गिरफ्तार किया है।

राहुल गांधी की केंद्र से अपीलः लद्दाख में हिंसा-भय की राजनीति बंद हो, बातचीत से समस्या का हल निकले

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र से लद्दाख के लोगों से बातचीत करने का आग्रह किया। उन्होंने सरकार से बातचीत करने और हिंसा व भय को राजनीति बंद करने का आह्वान किया। उन्होंने लेह में हुई हालिया हिंसा की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की, जिसमें चार लोगों की जान चली गई। एक्स पर एक पोस्ट में, राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि गोली लगने से मारे गए लोगों में से एक सैनिक परिवार से था। उन्होंने कहा, पिता सैनिक, बेटा भी सैनिक - जिनके खून में देशभक्ति दौड़ती है। फिर भी भाजपा सरकार ने देश के वीर सपूत की सिर्फ इसलिए गोली मारकर जान ले ली, क्योंकि वह लद्दाख और उसके अधिकारों के लिए खड़ा था। पिता की दर्द भरी आँखें बस एक ही सवाल पूछ रही है - क्या आज देश सेवा का यही इनाम है? राहुल ने निष्पक्ष न्यायिक जाँच की माँग को आगे बढ़ाते हुए इस मौत को हत्या बताया और कहा, हमारी माँग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जाँच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लद्दाख के लोग अपने अधिकारों की माँग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वे अपने अधिकारों की माँग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं - हिंसा और भय की राजनीति बंद करें। इससे पहले, 24 सितंबर को लेह में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जब स्थानीय भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई थी। इस झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी।

सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयानः कहा-

डीजीपी के आरोप झूठे... ये साजिश है, सरकार बना रही बलि का बकरा

लेह। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों पर उनकी पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने ऐतराज जताया है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक के बयानों को झूठा और गढ़े गई कहानी बताते हुए कहा कि यह एक सोची-समझी साजिश है, जिसके जरिए किसी को फंसाकर मनमर्जी करने की कोशिश हो रही है। गीतांजलि ने कहा, हम डीजीपी के बयान को कड़ी निंदा करते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि पूरा लद्दाख इन आरोपों को खारिज करता है। ये एक बनावटी कहानी है, ताकि किसी को बलि का बकरा बनाया जा सके और वे जो चाहें वो कर सकें। उन्होंने सवाल उठाया कि सीआरपीएफ को गोली चलाने का आदेश किसने दिया? अपने ही नागरिकों पर गोली कौन चलाता है? खासकर वहां, जहां कभी हिंसक प्रदर्शन नहीं हुए। गीतांजलि का कहना है कि सोनम वांगचुक का इस पूरी घटना से कोई लेना-देना नहीं था। वे तो उस समय किसी और जगह शांतिपूर्वक भूख हड़ताल पर बैठे थे। वे वहां मौजूद ही नहीं थे, तो वे किसी को कैसे उकसा सकते हैं? आरोप लगाया कि प्रशासन का मकसद छठे शेड्यूल को लागू न करना है, और इसके लिए एक झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। डीजीपी जो कुछ भी कह रहे हैं, वो एक एजेंडे का हिस्सा है। वे किसी भी हालत में 6वां शेड्यूल लागू नहीं करना चाहते और अब किसी को बलि का बकरा बना रहे हैं।

पाकिस्तान के क्वेटा में जबरदस्त धमाका, दस की मौत और 15 से यादा घायल; अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित

क्वेटा। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में जबरदस्त विस्फोट हुआ है, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है। धमाके में कई लोग घायल भी हुए हैं। क्वेटा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने बताया कि बम विस्फोट के चलते क्वेटा के अस्पतालों में आपातकाल लागू कर दिया गया है। सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों आदि को ड्यूटी पर मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, बम धमाका क्वेटा की जरगून रोड के करीब हुआ। धमाके में कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर है और 15 अन्य घायल हुए हैं। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य विभाग के मीडिया संयोजक ने बताया कि घायलों को सिविल

अस्पताल समेत विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बम धमाके का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक व्यस्त सड़क पर अचानक तेज धमाका हुआ, जिसकी चपेट में सड़क पर मौजूद कई लोग आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह एक आत्मघाती धमाका है। गौरतलब है कि बीती 4 सितंबर को भी क्वेटा में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुए बम धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से यादा लोग घायल हुए थे।

भगदड़ के बाद पहली बार एक्टर विजय ने तोड़ी चुप्पी, कहा-ऐसा दर्द कभी नहीं सहा

चेन्नई।

तमिलनाडु के करूर में अपनी रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत के दो दिन बाद, अभिनेता विजय ने आज एक शोक संदेश जारी किया. उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दर्दनाक स्थिति का सामना नहीं किया... मेरा मन चिंता से भर गया है और मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है. इससे पहले विजय पीड़ितों के लिए 20 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर चुके हैं. उन्होंने इस दुखद हादसे की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए कहा, हमें सच्चाई सामने लाने की जरूरत है ताकि ऐसा हादसा दोबारा न हो.

प्रशांत किशोर की पार्टी ने अब प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, सम्राट चौधरी पर तत्काल कार्रवाई की मांग

पटना। जन सुराज पार्टी (जसुपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को ही प्रेस-वार्ता कर कहा था कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। ग़ौरतलब, इस बीच चुनावी शपथ-पत्रों के आधार पर भाजपा की ओर से उदय सिंह की उम्र में भी घटतौली का आक्षेप लगाया गया है। उदय सिंह ने लिखा है कि सरकारी रिकार्ड के अनुसार, सम्राट चौधरी का नाम 28 मार्च 1995 को हुए लौना परसा नरसंहार (केस संख्या 44/1995, थाना तारापुर) में अभियुक्त के रूप में दर्ज है, तब

कुशवाहा समुदाय के छह लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में सम्राट चौधरी सहित छह अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सम्राट कई महीनों तक जेल में रहे, उनकी जमानत अर्जी दो बार निरस्त हुई थी। उन्होंने मैट्रिक (हाई स्कूल) के प्रवेश-पत्र के आधार पर अपनी उम्र 15 वर्ष सिद्ध की और नाबालिग का दर्जा पाकर रिहा हो गए। बाद के चुनावी हलफनामों में उन्होंने अपना जन्मवर्ष 1969 बताया, जिससे 2020 में उनकी उम्र 51 वर्ष हो जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि सन 1995 में उनकी उम्र 26 वर्ष थी, यानी वे नाबालिग नहीं थे। यह विरोधाभास इस बात का भी संकेत है कि गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर सम्राट की जेल से रिहाई कराई गई और एक गंभीर अपराध से उन्हें बचाने का प्रयास हुआ। इस प्रकार के व्यक्ति का उच्च पद पर बने रहना न केवल शासन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि कानून के राज और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास भी कम करता है। इसलिए विनय अनुरोध है कि सम्राट को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और कानून को अपना स्वाभाविक मार्ग अपनाने दिया जाए, ताकि उस नरसंहार के पीड़ितों को न्याय मिल सके। पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ऐसे मुद्दों को उचित गंभीरता एवं सत्य, न्याय एवं सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही की भावना के साथ सुलझाया जाएगा।

आई लव मुहम्मद : सीएम धामी का अल्टीमेटम, शांति भंग की तो चुकानी पड़ेगी कीमत

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को आई लव मुहम्मद लिखी तख्तियों के प्रदर्शन के खिलाफ चेतावनी दी और इसे त्योहारों और सार्वजनिक शांति भंग करने का एक सुनियोजित प्रयास बताया।

इस विवाद पर बोलते हुए, धामी ने कहा कि यह हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अशांति और अशांति पैदा करने के उद्देश्य से एक सोची-समझी साजिश है। इसके पीछे वे ताकतें हैं जो भारत को मजबूत होते नहीं देख सकतीं... जो प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में विकसित भारत के संकल्प में तो रोड़े विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर आप किसी से जुड़े हैं, तो आपको उनके नाम की तख्ती लेकर घूमने का अधिकार

किसने दिया? अगर आप किसी से प्यार और सम्मान करते हैं, तो वह सम्मान तभी सच्चा होता है जब वह आपके व्यवहार में झलकता है। धामी ने यह भी चेतावनी दी कि अशांति के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी व्यक्ति से इसकी कीमत वसूल की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, इस धरती (उत्तराखंड) पर इस तरह की अराजकता कतई नहीं की जाएगी। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी...चाहे वह सरकारी संपत्ति हो या निजी, दंगाई कोई भी हो, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी और यह बहुत सख्ती से किया जाएगा।

केंद्र ने अब तक नहीं दी 260 करोड़ रुपए की मदद, वायनाड भूस्खलन पर केरल सीएम का बड़ा आरोप

तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने वायनाड भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के लिए 260.65 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है, लेकिन राज्य को अब तक यह धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। यह बयान उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने शुरुआती आकलन के आधार पर केंद्र से 2,262 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसके बाद विस्तृत पोस्ट-डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए) रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें लगभग 2221.10 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया। इस रिपोर्ट में मृतकों के आश्रितों, आजीविका गंवाने वालों और पुनर्वास की लागत का आकलन शामिल था। विजयन ने कहा कि इस मामले पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) की उप-समिति ने विचार किया और राज्य स्तरीय समिति के साथ बैठक भी की। समिति में मुख्य सचिव डॉ. ए. जयतिलक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। चर्चाओं के बाद यह तय हुआ कि केंद्र से 260.65 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन अभी तक यह राशि राज्य को

नहीं मिली है मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि केरल ने केंद्र से वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा और गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित करने की मांग की थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धारा 13 को बदलने की अपील की गई थी ताकि पीड़ितों के लिए ऋण माफी संभव हो सके। लेकिन इस पर अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। विजयन ने कहा कि सरकार ने एल्स्टन एस्टेट की 64.475 हेक्टेयर भूमि पर पीड़ितों के लिए टाउनशिप परियोजना शुरू की है। अब तक 295 लाभार्थियों ने नए घरों में शिफ्ट होने की सहमति दी है, जबकि अपील की जांच के बाद 49 और नाम इस सूची में जोड़े गए हैं। यह परियोजना जनवरी 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। वायनाड जिले के मुण्डक्कई और चूरलमला क्षेत्रों में 30 जुलाई 2023 को आए भूस्खलन में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। इस आपदा ने पूरे क्षेत्र को लगभग तबाह कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता से पुनर्वास कार्य में जुटी है और केंद्र से अपेक्षित सहयोग मिलने पर कार्य और तेज होगा।